अपराध आरोपणीय दस्तावेज बरामद हुए थे। शुल्क छूट हकदारी प्रमाणपत्र योजना के तहत आयातित खेपों की जांच पड़ताल करने और उनका आगे और दुरुपयोग न होने देने के लिए उन्हें रोक लिया गया है। लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को निर्यातकर्ताओं के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई शुरू करने हेतु सूचित कर दिया गया है।

एक मामले में शतप्रतिशत निर्यातोन्मुखी उपक्रमों को प्रदान की गई सुविधाओं का दुरुपयोग किए जाने का पता चला था। यह मामला न्यायनिर्णयाधीन है। इसी बीच, ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति न होने देने के लिए कर्मचारियों को अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

अन्य दो मामलों में से एक मामले में आयातित माल के न्यून बीजकांकन के जरिए तथा दूसरे मामले में अग्रिम लाइसेंस के प्रति माल की निःशुल्क निकासी का दावा करके किए गए सीमा शुल्क अपवंचन का पता लगाया गया था। जांच पड़ताल चल रही है और मामलों का न्यायनिर्णयन किया जाएगा। भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न होने पाए इसके लिए कर्मचारियों को सतर्क कर दिया गया है।

Issue of Bonds by SBI for Non-Resident Indians

3879. SHRI BHAGATRAM MANHAR :
SHRI DHULESHWAR MEENA :
SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH :

Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the State Bank of India have decided to issue a series of non repatriable bonds for Non-Resident Indian shortly ;

(b) if so, what are the details in this regard ; and

(c) what would be the maturity period of the above bonds and what would be the rate of interest allowed on the above bonds and to what extent these bonds will be useful for the investors ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI EDUARDO FALEIRO) . (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Government have designated the State Bank of India to issue foreign currency denominated Bonds for subscription by Non-Resident Indians on non-repatriation basis The maturity period of these Bonds will be seven years and they will carry interest rate slightly higher than that applicable to rapatriable foreign currency deposits. These bonds will provide an additional avenue to the NRIs to keep their savings in India.

Bungling in the State Bank of Indore

3880. DR. BAPU KALDATE : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the then Branch Manager of Connaught Circus. New Delhi Branch of State Bank of Indore had drawn money illegally from the Bank as loan in the names of his relations during the period 1981-83; if so, what is the amount of such loans; and

(b) if so, what are the details in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI EDUARDO FALEIRO) : (a) and (b) State Bank of Indore has reported that it is not a fact that the then

Branch Manager of Connaught Circus, New Delhi branch had drawn money illegally from the bank as loan in the name of his relatives during the period 1981-83. He had, however, sanctioned during this period credit facilities amounting to Rs. 95,000/- to a firm, in which one of his relatives was partner, for genuine business requirements. However, as prior permission of controlling authority was not obtained by the officer he has been awarded punishment of 'censure'. The bank has also intimated that the loan sanctioned has since been liquidated.

उत्तर प्रदेश हथकरघा निगम के प्रबंधकों द्वारा राजसहायता प्राप्त मर्दानी धोतियों की बिक्री में अनियमितताएं

3881. **श्री मोहम्मद अमीन** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार हथकरघा निगम को मर्दानी धोतियों के निर्माण के लिए राजसहायता प्रदान करती है और क्या ये धोतियां गरीब लोगों तक नहीं पहुंचती हैं और काले बाजार में बेच दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार अनिवार्य वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत इन लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करेगी; और

(ग) सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश हथकरघा निगम में बड़े पैमाने पर व्याप्त इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्री श्री राम निवास मिर्धा : (क) केन्द्र सरकार जनता कपड़ा योजना चलाती रही है। इस के दो उद्देश्य है : बेरोजगार तथा अर्ध रोजगार प्राप्त बुनकरों को लगातार रोजगार प्रदान करना तथा गरीब जनता को कम कीमतों पर कपड़ा उपलब्ध कराना। इस समय इस योजना के अन्तर्गत कपड़े के उत्पादन पर 2.75 रु० प्रति वर्ग मिटर की दर से आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना के अंतर्गत निर्मित कपड़े के वितरण सहित योजना के सारे क्रियान्वयन के लिए विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त सरकार ने निर्धारित किए हैं चूंकि योजना को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, इस लिए यदि कोई शिकायतें प्राप्त होती है, तो उन्हें आवश्यक कार्यवाही के लिए राज्य सरकार के पास भेज दिया जाता है। जनता धोती की काला बाजारी के सम्बन्ध में कोई ऐसी निश्चित शिकायत केन्द्र सरकार को नहीं मिली है जिसका सत्यापन हो सके।

(ख) जनता कपड़ा योजना के अन्तर्गत निर्मित कपड़ा आवश्यक वस्तु अधिनियम की परिधि में नहीं आता है।

(ग) सरकार इन मामलों में उपयुक्त कार्यवाही करेगी जिनमें अनियमितताओं के निश्चित उदाहरण उसकी जानकारी में लाए जाएंगे।

Centre's Intervention sought for the matter pertaining to the liquidation of machinery manufacturing corporation

3882. SHRI SURESH KALMADI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Maharashtra Government has requested the Central Government to intervene in the liquidation matter of Machinery Manufacturing Corporation; and

(b) if so, what are the details thereof and what action the Central Government have taken in the matter ?